



# आरत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114]

नई विल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1969/श्रावण 3, 1891

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1969/SRAVANA 3, 1891

इस भाग में विज्ञ पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह घरगुच्छ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th July 1969

No. LEI(A)-16(2)/68.—The Tariff Commission has submitted its Report on the price structure of catguts on the basis of an enquiry undertaken by it under Section 12(d) of the Tariff Commission Act, 1951. Its recommendations are as follows:—

- (i) The domestic demand for catguts is of the order of 250,000 dozen for the current year (1968) going up at the rate of about 16,000 dozen annually and reaching the level of 300,000 dozen in the year 1971.
- (ii) It would be desirable for the manufacturers to introduce as early as possible the irradiation method of sterilisation of catguts.
- (iii) Tests regarding absorbability, tensile strength, uniformity of gauge and other similar specifications of undisputed therapeutic importance may be included in the Indian Pharmacopoeia.
- (iv) Needled sutures may be excluded from price control for some time in order to provide a certain degree of freedom for the development of this infant branch of the industry.
- (v) The price recommended for plain and chromic sutures for 1969 and 1970 is Rs. 27.25 for destination per dozen tubes,

2. Government have taken note of recommendation (i) which is an observation made by the Commission and accept recommendations (ii), (iii) & (v) and suitable action will be taken to implement them to the extent practicable.

3. The recommendation (iv) was further examined in consultation with the Tariff Commission who have since expressed that they have no objection to keep control on prices of Needled sutures provided the objective underlying their recommendation for decontrol is kept in view. Government accept the Commission's recommendation of prices of different codes of Needled sutures which are indicated below and have taken note of their observation for development of this branch of industry for appropriate action.

S. No.	Codes	F.O.R. destination price per dozen Rs./Doz.
1.	<i>Straight &amp; Curved Needles—'A' Pack:</i> (a) M.400, M.404, M.405, M.407, M.408 M.409, M.410, M.412, M.413, G.102 (b) M.416, M.417, G.113 G.114	34.41 34.41
2.	<i>Curved Needles—'B' Pack:</i> (a) M.420, M.421, M.423, M.424, M.425, M.426 (b) M.441, M.442, G.123, G.124	36.26 36.26
3.	<i>Half Circle Needles—'C' Pack:</i> M.445, M.446, M.449, M.450, 863, 864	37.84
4.	<i>Half Circle Needles—'A' Pack:</i> M.437	50.60
5.	<i>Half Circl Needles—'B' Pack:</i> M. 438	51.46
6.	<i>Curyed and Half Circle Needles—'A' Pack:</i> (a) M.470 (b) M.471	56.01 56.01
7.	<i>Curved Needles—'A' Pack:</i> (a) M.510 (b) M.520	55.40 55.40

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

श्रीधोगिक विकास, आमतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(श्रीधोगिक विकास विभाग)

संकलप

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1969

सं०एल०ई०आई०(ए) 16(2)/68.—प्रशुल्क आयोग ने प्रशुल्क आयोग अधिनियम 1951 की धारा 12ब के अन्तर्गत कराई गई जांच के आधार पर तांतों के मूल्य ढाँचे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारियों निम्नलिखित है :—

(i) तांतों की वेशी मांग चालू घण्ठ (1968) में 250,000 दर्जन के मुकाबिले लगभग 16,000 घण्ठन आवधि तक और बढ़ गई है और जिसके 1971 तक 300,000 दर्जन तक पहुच जाने की आशा है।

- (ii) तांत्रों के अनुचरीकरण की किरणीयन विधि को यथाशीघ्र व्यापक करना निर्माताओं के लिए बांछनीय होगा ।
- (iii) अवशोषणीयता, तनाव धमता, मापक एकल्पता सम्बन्धी परीक्षण तथा इस प्रकार के अन्य चिकित्सा विषयक परीक्षणों को भारतीय भेषजीय सूची पत्र में शामिल किया जाए ।
- (iv) धाव पर टांका लगाने हेतु सूचर पर से नियंत्रण कुछ समय तक के लिए हटा लिया जाना चाहिए जिससे कि इस उद्योग प्रारम्भिक अवस्था में कुछ हद तक विकसित करने में स्वतन्त्रता दी जा सके ।
- (v) 1969-70 के लिए सारे तथा औमिक सूचरों के प्रति दर्जन ट्यूबों का निर्दिष्ट स्थान पर गाड़ी भाड़ा मुक्त मूल्य 27.25 रु. है ।

2. सरकार ने सिफारिश पर ध्यान दिया है (1) यह आयोग द्वारा किया गया अवलोकन है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है (2) (3) और (4) सिफारिशों स्वीकार कर ली गई हैं वहाँ व्यावहारिक होगा उन्हें लागू करने के लिए उचित कार्यवाही की जायगी ।

3. प्रशुल्क आयोग के परामर्श से सिफारिश (4) पर फिर से विचार किया गया उम का यह कथन है कि धावों पर टांका लगाने वाले सूचरों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखे जाने के बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि नियंत्रण हटाने के लिए की गई उनकी सिफारिश के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए । सरकार धावों पर टांका लगाने वाले विभिन्न वर्गों के सूचरों के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस उद्योग का विकास करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए उनकी आपत्ति पर ध्यान दे रही है ।

क्र०सं०

वर्ग

प्रति दर्जन एक०  
ओ० आर० निर्दिष्ट  
मूल्य

रु०/ दर्जन

## 1. सीधी तथा टेढ़ी सुइयां

'ए' मैक

- (क) एम० 400, एम० 404, एम० 405, एम० 407, एम० 408, एम० 409, एम० 410, एम० 412, एम० 413 बी० 102 . . . . . 34.41
- (ख) एम० 416, एम० 417, जी० 113, जी० 114 . . . . . 34.41

## 2. टेढ़ी सुइयां-बी०पैक

- (क) एम० 420, एम० 421, एम० 423, एम० 424, एम० 425, एम० 426 . . . . . 36.26
- (ख) एम० 441, एम० 442, जी० 123, जी० 124 . . . . . 36.26

क्र० सं०

वर्ग

प्रति दर्जन एक०  
 श्रो० अ. र० निर्दिष्ट  
 मूल्य

3.	अधीकार सुइयां—“सी” पैक							37. 84
	एम० 445, एम० 446, एम० 449, एम० 450, 863, 864 .	.	.	.	.	.	.	
4.	अधीकार सुइयां—“ए०” पैक							50. 60
	एम० 437 .	.	.	.	.	.	.	
5.	अधीकार सुइयां—‘बी’ पैक							41. 46
	एम० 438 .	.	.	.	.	.	.	
6.	टेढ़ी तथा अधीकार सुइयां—‘ए’ पैक							
	(क) एम० 470 .	.	.	.	.	.	.	56. 01
	(ख) एम० 471 .	.	.	.	.	.	.	56. 01
7.	टेढ़ी सुइयां—‘ए’ पैक							
	(क) एम० 510 .	.	.	.	.	.	.	55. 40
	(ख) एम० 520 .	.	.	.	.	.	.	55. 40

## प्रावेश

प्रावेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ० आर० सुन्दरम्,  
संयुक्त सचिव।